

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण
तथा वक्फ विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून

दिनांक 07 दिसम्बर 2010

विषय:—वित्तीय वर्ष 2010-11 में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को विकास कार्यो के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून के पत्रांक:—558 दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अल्पसंख्यक कल्याण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के विकास कार्यो के संचालन हेतु सहायता के आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित ₹ 04.72 लाख (₹ चार लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:—187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा।
2. उक्त मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें, -00-800-अन्य व्यय, 08-अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को विकास कार्यों के संचालन हेतु सहायता के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:-732(P)/XXVII(1)/2010 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(बी0आर0 टम्टा)

अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1445 (1)/XVII-3/10-06(Budget)/10 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, समाज कल्याण, हल्द्वानी-नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादू
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)

अनु सचिव।